ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 133-134
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

महिलाओं का बदलता ग्रामीण परिवेश और डिजिटल प्रौद्योगिकी

1. राजेश त्रिपाठी 2. श्रीमती शैल्या सिंह

1. एसोसिएट प्रोफेसर–समाजशास्त्र विभाग 2. शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र, मा.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

Received- 30.09. 2019, Revised- 06.10.2019, Accepted - 11.10.2019 E-mail: vishnucktd@gmail.com

सारांश : **ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार में अभूतपूर्व वृद्धि होने से इन क्षेत्रों के रूपान्तरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ग्रामीण भारत पर डिजिटल क्रांति का प्रभाव समझने विशेष रूप से कौशल और रोजगार के मामले में इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिये इस प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए नवीन दृष्टिकोण और एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। आज जिस तरह शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और अन्य जन सेवायें प्रदान की जा रही है। उसमें प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण बदलाव लाने में प्रमुख भूमि अदा कर रही है। यह शिक्षित और अशिक्षित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच अंतराल समाप्त करने में भी इसकी भूमिका है।**

कुंजी शब्द – डिजीटल, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण भारत, डिजिटल क्रांति, कौशल, रोजगार, कार्यान्वयन, शिक्षित।

ग्रामीण भारत में शिक्षा और रोजगार का परिदृश्य देखा जाये तो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक बल में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। उपलब्ध आँकड़ों से 2012–13 की 3.5 प्रतिशत घटकर 2015–16 में 34 प्रतिशत रह गयी यानी महिलाओं का योगदान करीब 21 प्रतिशत रह गया है। ग्रामीण क्षेत्रो में महिलाएँ मुख्यतः हस्तशिल्पों, हथकरघा, बुनियादी खाद्य प्रसंस्करण और पापड़ कला तथा आचार बनाने जैसे सूक्ष्म उद्यमों आदि में संलग्न है। उनकी सीमित सामाजिक गतिशीलता अक्सर उन्हें रोजगार और कौशल विकास के अवसरों में शामिल होने से रोकती है।

डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ग्रामीण भारत की क्षमता का विस्तार 2014 में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों को एक बुनियादी सेवा के रूप में हाई स्पीड इण्टरनेट की सुविधा प्रदान करने उन्हें एक विशिष्ट जीवन पर्यन्त ऑनाइन और प्रमाणिक पहचान देने मोबाइल फोन और बैंक खाता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षारता अभियान मार्च 2019 तक ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षारता का प्रसार करना और 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रमुख व्यवसाय है– जैसे–

1. निवेश सामग्री के वितरण में कमी,
2. औषत मूल्य और व्यापार नीतियों के कारण खेती में बढ़ते जोखिम,
3. जोत क्षेत्रों का आकार छोटा होना,
4. बाजार अक्षमतायें बढ़ते जाने और कृषि कचरे में बढोत्तरी होने,
5. गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित होने है।

विश्व भर में प्रौद्योगिकी ने कार्य क्षमता में सुधार लाने और कृषि व्यापार के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागत में कमी लाने में योगदान किया है। सभी ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं विशेषकर युवाओं की डिजिटल साक्षारता में बढोत्तरी हुई है। ई–कामर्स, ई–लर्निंग, ई–बैंकिंग आदि सेवाओं के संचालन के रूप में रोजगार के नये अवसरों का सृजन हुआ है।

कॉमन सर्विस सेन्टरों का नेटवर्क छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से अधिक डिजिटल सेवायें प्रदान कर रहा है। इनमें आधार पंजिकरण, टिकट बुकिंग सेवाओं से सम्बन्धित बिलों का भुगतान कौशल सम्बन्धी सेवाएँ डिजिटल साक्ष्ज्ञरता आदि शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि देशभर में कार्यरत 2.05 लाख कामन सर्विस सेण्टर ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक युवाओं के लिये रोजगार के अवसर पहले ही सृजित कर चुके है। इसमें 34000 से अधिक महिलाएँ शामिल है। स्वयं शिक्षण प्रयोग के एक कार्यक्रम आरोग्य सखी के जरिये ग्रामीण महिला उद्यमी एक मोबाइल अप्लीकेशन की मदद से गाँवों में लोगों की दहलीज पर निवारण स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करती है। ग्रामीण शीर्ष के अन्तर्गत लगभग 50 प्रतिशत महिलायें रोजगार प्रदान कर चुकी है।

कौशल विकास कार्यक्रमों का उन्नयन सुविधाओं के अभाव वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल समितियों और कौशल वर्धन केन्द्रों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के जरिये महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती है। जो स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले युवाओं और महिलाओं का प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

राज्य सरकारों को ग्रामीण संस्थानों जैसे पंचायत संस्थाओं, कॉन सर्विस सेण्टरों स्व सहायता समूहों, सहकारी

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

संस्थाओं, कृषक उत्पादक संगठनों, कृषि समितियो, गैर सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों, भारतीय डाक उर्वरक निगम आदि को उन्नत बनाना चाहिये, तॉकि वे इस क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा और सरकार के विभिन्न उपायों की आवश्यकता के प्रति व्यापक जागरुकता पैदा करें।

महिलाओं की गैर परम्परागत कौशल क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रीशिन, बेल्डिंग राजगिरि, मैकेनिक्स, प्लम्बर, पम्पों, टेलीविजन, सेंटों मोबाइल फोनों की मरम्म्त जैसे कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए सजग प्रयास किये जाने चाहिये। कम्प्यूटरों के इस्तेमाल, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी अप्लीकेशनों में महिलाओं की प्रशिक्षण देने की दिहाड़ी और स्वरोजगार दोनों ही दृष्टियों से उनकी रोजगार सहायता बढ़ाई जा सकती है।

स्वयं सहायता समूह भारत में नई सामाजिक अर्थव्यवस्था के उभरने का उदाहरण है। इन स्वयं सहायता समूहों की और मजबूत करने और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे सामूहिक ग्रामीण उद्यमशीलता का प्रारूप है, जो ग्रामीण नागरिकों विशेषकर महिलाओं के लिये सतत आय सृजित कर सकते हैं। ग्रामीण लोगों विशेषकर युवाओं और महिलाओं को शिक्षित बनाने से उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यम स्थापित करने और उनका विकास करने में सक्षम बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत सरकार ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व में अधिक आजीविका स्टोर खोलने की योजना बना रही है। तॉकि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचने के लिये उन्हें बिक्री केन्द्र प्रदान किये जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास सम्बन्धी उत्कृष्ट पद्धतियों के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा किये गये उपायों से सम्बन्धित सफलता की कहानियाँ।नवाचारों के उपायों को स्थानीय निकायों/साझा किया जा सकें। इसमें इन प्रयासों को उन्नत बनाने और उनका अनुसरण करने में मदद मिलेगी। कौशल विकास और उन्न्यन पुरुषों और महिलाओं विशेषकर युवाओं की रोगार सक्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

कौशल विकास और उन्न्यन पुरुषों और महिलाओं विशेषकर युवाओं की रोजगार सक्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। एक जुट और तीव्र प्रयासों के जरिये यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और रोजगार की व्यापक संभावनाओं का दोहन कर सकें और साथ ही वर्तमान रोजगार का स्तर बढ़ा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दोषी एस.एल. (2002) ''आधुनिकता, उत्तर–आधुनिकता एवं नव–समाजशास्त्रीय सिद्धांत'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली
2. देसाई नीरा, ठक्कर ऊषा (2008), ''भारतीय समाज में महिलाएँ'' नेहरू भवन 5, बसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–2, बसंत कुंज, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित।
3. पाण्डेय डॉ. रविप्रकाश (2011), ''वैश्वीकरण एवं समाज'' शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. लवानिया डॉ. एम.एम. जैन शशि के., (2007) ''ग्रामीण समाजशास्त्र'' रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर नई दिल्ली।
5. हसनैन नदीम, (2004), ''समकालीन भारतीय समाज'' एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य, शिवानी आर्ट, प्रेस नवीन शाहदरा, दिल्ली।
6. सिंह प्रो.योगेन्द्र (2002), ''भारतीय परम्पराओं का आधुनिकीकरण'', जवाहर पब्लिशर्स बेरसराय, नई दिल्ली।

*****